आम लोग जो मजदूर-पेशा है, वेज-अर्नर है, गरीब तबका है, उनके पास इतना समय नहीं कि वह दर्खास्त देकर शिकायत करें। वह कभी ऐसा करने की पोजीशन में नहीं हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा तरीका निकालेगी, कोई मशीनरी रखेंगे जिसके जरिये से वह पता लगा सकेंगे कि एडल्ट्रेशन कहां होता है ताकि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।

राव बीरेन्द्र सिंह : जो एक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उनका इम्पलीमेंटेशन, उनका एनफोर्समेंट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। उनके पास भारी मशीनरी इस काम के लिए है, बहुत से इंसपैक्टर्ज फूड सप्लाई के होते हैं हर जगह। उनका काम है कि जगह-जगह जाकर चैकिंग करें, छापे मारें और एक्शन लें, चालान करें और अदालतों से सजा दिलावायें। हमारे पास, जैसा मैंने कहा कि कोई एजेन्सी नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो जिम्मेदारी स्टेट सरकारों की है, वह जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकती। इसमें जो स्टेट की जिम्मेदारी है, वह स्टेट को ही निभानी पड़गी। हम उनके काम में, इस मामले में दखल नहीं कर सकते।

सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कानून बनाने की है इस पार्लियामेंट की तरफ से और उसके बाद हम उनकी देखभाल जरूर करते हैं। उनको हिदायतें देते है, गाईडेंस देते है। उसके बाद उनका काम है कि किस तरीके से तनदहीं से वह मिलावट को रोकें।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : आप जो मशीनरी को हिदायतें.... (**व्यवधान**), वह तो बता सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : जी, हां, वह हिदायतें बराबर देते रहते है।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : वह तो आपने बताया नहीं है कि क्या हिदायतें देते हैं उन्हे।

MR. CHAIRMAN: Next Question. Question No. 350, Mr. Suraj Prasad.

Industrial Accidents

‡*350. SHRI SURAJ PRASAD:†

SHRI INDRADEEP SINHA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that industrial accidents have increased in the recent past;

(b) what were the industrial accidents during the years 1982-83, 1983-84 and 1984-85; and

(c) what steps Government have taken to prevent such accidents?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The following table gives the number of fatal and non-fatal injuries, which resulted on account of industrial accidents, in the years 1981, 1982 and 1983. The figures for the year 1984 are yet to be finally compiled.

Year	No. of Injuries			Percentage increase over last year
	Fatal	Non-fatal	Total	
1981	687	332885	333572	+5.4
1982	757	345686	346443	+3.9
1983	864	348390	349254	+0.81

†The question was actually on the floor of the House by Shri Suraj Prasad.

‡Previously Starred Question 290, transfered from the 12th August, 1985.

It would be seen that although in absolute numbers the figures relating to accident showed a merginal increase there has been a fall in the rate of increase of accidents over the last three years.

Government have advised the State Governments/Administrations of Union Territories to augment the staff in their Factory Inspectorates, streamline procedures, update Factory Rules by incorporating all the provisions of the Model Rules and Schedules recommended by Government and also to carry out more frequent inspection of factories, working of which are prone to accidents/diseases. To facilitate proper monitoring and prompt preventive action, a Safety And Health Accident Reduction Action Plan has been recommended to all State Governments/ Administrations/Employers and Workers Organisations for adopting the same in manufacturing units which are hazardous.

The Labour Ministers' Conference held on 11th May, 1985 also considered various aspects of safety and health of workers and measures to be taken in this regard. The Conference made a number of recommendations in this regard. One of the recommendations of the Conference is that the Factories Act, 1948 should be amended to include a special chapter to deal with safety in hazardous industries. The Conference also recommended that penalty for continued violation of safety regulations in hazardous industries should be compulsory imprisonment. Government is considering appropriate amendments to the Factories Act, 1948.

श्री सूरज प्रसाद : महोदय, जो स्टेटमेंट सरकार ने रखा है, उसको देखने से यह पता चलता है कि फेटल और नान-फेटल दोनों तरह की घटनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और खास करके फेटल की संख्या में वृद्धि चिंतनीय है, 687 से 864 हो गये हैं ।

इससे यह लगता है कि फैक्टरी के जो नियम हैं, उन नियमों का पालन—सेफटी मेजर्ज के जो नियम हैं, उनका पालन कारखानों द्वारा नहीं हो रहा है और साथ ही साथ जो इंसपैक्टर्ज होते है, जो इन फैक्टरीज की जांच करते हैं, उनके द्वारा ठीक से निरीक्षण भी नहीं हो रहा है । ऐसी स्थिति में सरकार ने यह कहा है कि हमने राज्य सरकारों को यह एडवाइज किया है, डाइरेक्शन नहीं एडवाईज किया है, कि वे इसके संबंध में उचित कदम उठायें ताकि जो एक्सिडेंट्स हो रहे हैं, उनमें कमी लाई जा सके ।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने राज्य सरकारों को इस संबंध में कब निर्देश दिये और किन राज्य सरकारों ने इस नियम का पालन किया है और किन राज्यों ने इस नियम का पालन नहीं किया है ?

श्री टी० अन्जैय्या : तमाम सरकारों को यह कहा गया है—जो स्टेट गवर्नमेंटस हैं, कि यह बहुत जल्दी सेफटी एक्ट के बारे में. भारत सरकार जो—है—भोपाल काण्ड के बादि हम लोगों ने यह डिसीजन लिया कि इस का बहुत सख्ती के साथ इम्पलीमेंटेशन करायेंगे । और टास्क फोर्स बनाने के लिए उन्होंने हमें कहा है कि बहुत सी राज्य सरकारों—महाराष्ट्र और तामिलनाडू आदि सरकारों ने हमें जवाब दिया है, वह टास्क फोर्स बना रही हैं और उसके ऊपर से हम लोग एक मीटिंग करके जो इसके अन्दर एक्सपर्टस हैं वह उन एक्सपर्ट्स के साथ यह कमेटीज बनेंगी, फैक्ट्री एक्ट के अन्दर भी काफी चेंजेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, सजा भी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। सारी चीजों को दोबारा सोच रहे हैं ।

श्री सूरज प्रसाद : महोदय, सरकार ने यह कहा है कि फैक्ट्री एक्ट में हम संशोधन पर विचार कर रहे हैं, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार फैक्ट्री एक्ट में संशोधन के लिए कब कानून पेश करने वाली है, ताकि जो दुर्घटनाएं हो रही है उनको रोकने में कुछ सफलता हासिल की जा सके ?

श्री टी० अन्जैय्या : अभी लेबर मिनिस्टरों की कान्फ्रेंस में इस बात की चर्चा हुई है और भी लोग बैठ रहे है और अक्तूबर-नवम्बर के अन्दर इसमें काफी एमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है, वह हो जायेंगे और हाउस के सामने भी लाया जायगा ।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Monika Das.

SHRIMATI MONIKA DAS. Mr. Chairman, Sir, according to the Employment of Children Act, 1938, children under 14 years cannot work in an industrial area or workshop area. Two -and-a-half million children are working in industrial areas.

MR. CHAIRMAN: Not relevant. Look at the question.

SHRIMATI MONIKA DAS. I am coming to the question.

MR. CHAIRMAN: I want you to come. But you are not coming. (*Interruptions*)

SHRIMATI MONIKA DAS: Does the Minister know that children are working in the industrial areas and they are losing their capability and are becoming handicapped? Is the Government giving any compensation for them and, if not, what action are they taking?

SHRI T. ANJAIAH: The Act is there. They are also covered by the insurance scheme. But so far as the Children Act is concerned, that is a separate question.

MR. CHAIRMAN: Next question.

*351. [The questioner (Shri M. Kadharsha) was absent for answer vide col 43—44 *infra*].

*352. [The questioner (Shri Dipen Ghosh) was absent. For answer vide ol. 44-48 infra].

MR. CHAIRMAN: Question No. 352. Mr. Dipen Ghosh. Not here.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: The Prime Minister has called him.

MR. CHAIRMAN: Next question, Shri Biswa Goswami.

Grants for Poultry, Fish Culture, Animal Husbandry etc.

×

*353. SHRI BISWA GOSWAMI:
SHRI HUKMDEO NARAYAN YADAV:

Will the Minister of AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that grants are given alongwith loans for fish culture, poultry farming, piggery and animal husbandry, if so, what amount was sanctioned as grants during the last three years under these schemes, State-wise, and what was the number of such schemes;

(b) what is the number of those persons amongst the beneficiaries who secured a loan of more than rupees one lakh; and

(c) whether it is also a fact that the amount of loan has not been spent on these schemes?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI BUTA SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Subsidies alongwith loans are provided (a) for rearing of cross-breed heifers, establishment of poultry, piggery and sheep production units under Special Livestock Production Programme (SLPP) and (b) only subsidy for fish culture under Fish Farmers' Development Agency Programmes (FFDA). Similarly subsidies and loans are given under Integrated Rural Development Programme (IRDP) for taking up income generating activities including fish farming, poultry farming, piggery, etc.

Two tables giving state-wise grants under Special Livestock Production Programme and Fish Farmers' Development Agency Programmes are given in the enclosed Statement-I and II respectively. (*See below*). No scheme-wise details of expenditure are available in respect of Integrated Rural Development Programme.

The loan component under all these schemes is obtained by the beneficiaries through financial institutions/banks.

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Biswa Goswami.